

विचार

सम्पादकीय

जुल्म की इबारत

इन प्रदर्शनों को देखकर लगता है कि लोग उस दौर के जुल्मों को भूले नहीं हैं और वे पिछले 20 वर्षों में मिली आजादी भी गंवाने के लिए तैयार नहीं हैं। इन विरोध प्रदर्शनों को जिस तरह से दबाने की कोशिश हुई, उसने नई और सूधीरी हुई छवि के तालिबान के दावों पर भी सवालिया निशान लगा दिया। अफगानिस्तान के जलालाबाद शहर में शांतिपूर्ण विरोध करते लोगों पर तालिबान द्वारा फायरिंग की घटना विचलित करती है। इस घटना में कम से कम तीन लोगों के मारे जाने और करीब एक दर्जन के घायल होने की सूचना है। नागरिकों की ओर से तालिबान के शांतिपूर्ण विरोध की खबरें कुछ अन्य शहरों से भी मिल रही हैं। काबुल में भी कुछ महिलाओं के हाथों में पोस्टर लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का विडियो वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें और विडियो बताते हैं कि हिंसा और दहशत का इतिहास रखने वाले तालिबान के खिलाफ वहां आवाजें उठ रही हैं और उससे यह बदर्शत नहीं हो रहा।

इससे यह भी पता चलता है कि तालिबान ने भले ही देश के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है, लेकिन सभी लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया है। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि पिछले 20 वर्षों में अफगानिस्तान में बड़े बदलाव आए थे। समाज में खुलापन आया था। लड़कियों को काम करने और पढ़ने की आजादी मिली थी। परदे में रहने की बंदिशें नहीं थीं। इस बीच, सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं बेहतर हुईं। अफगानिस्तान में 11 फीसदी लोगों की इंटरनेट तक पहुंच है, जो साल 2000 में शून्य फीसदी था। इन सबके बीच प्रशासन से लोगों की उम्मीदें भी बढ़ी हैं। वहीं, 1996-2001 के बीच जब तालिबान का देश पर राज था, तब अफगानिस्तान मध्ययुगीन दौर में चला गया था। औरतों पर तमाम बंदिशें थीं। पुरुषों को दाढ़ी रखनी पड़ती थी। अपराधों के लिए बीच सड़क पर सजा दी जाती थी। इन प्रदर्शनों को देखकर लगता है कि लोग उस दौर के जुल्म को भले ही हैं और वे पिछले 20 वर्षों में मिली आजादी भी गवाने के लिए तैयार नहीं हैं। इन विरोध प्रदर्शनों को जिस तरह से दबाने की कोशिश हुई, उसने नई और सुधरी हुई छवि के तालिबान के दावों पर भी सवालिया निशान लगा दिया। यूं तो राजधानी काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने देश भर में आम माफी का ऐलान किया। लोगों से बेखटके सामान्य जीवन जीने की अपील की। महिलाओं को शरीयत के मताबिक सरकार तक में हिस्सेदारी देने जैसी बातें भी कीं। लेकिन जलालाबाद की घटना से लगता है कि तालिबान बदला नहीं है, वह सिर्फ बदलने का दिखावा कर रहा है। वह भी इसलिए कि देश पर शासन करने के लिए उसे लोगों का समर्थन और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से स्वीकृति चाहिए। जलालाबाद और अन्य शहरों में अगर तालिबान ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन होने दिया होता तो शायद उसे उसके बदलने का संकेत माना जाता। वह दुनिया को दिखा सकता था कि तालिबान असहमति का सम्मान करना जानते हैं। मगर निहत्ये लोगों पर अंधाधूंध फायरिंग की यह घटना बताती है कि उसकी कथनी और करनी में काफी फर्क है। अभी तक के संकेत देखकर यह भी कहना मुश्किल है कि तालिबान बदल गया है।

हाले पूर्वांग दुनिया का एक जानकारी व्यवहार का उपयोग करता है। जो जमाने और उसे पुष्टित पल्लवित करने का श्रेय भी इन दो महाशक्तियों के नाम ही जायेगा। जो दुनिया की दो धूरीय व्यवस्था में एक दूसरे को निपटाने और एक दूसरे से आगे जाने के लिए बेकरार रहीं। दो धूरीय दुनिया अब तो नहीं रही इसलिए अब इस देश के लोगों को किसी की भी चिन्ता नहीं है। अमेरिका वर्षों से यहां कब्जा जमाकर बैठा था। अमेरिका और नाटो देश के सैनिकों ने फौजें वापस बुला ली हैं। पहली मई से अमेरिकी फौजों की वापसी शुरू हुई और तालिबानों के हमले बढ़ते गए। हालात इतने बिंगड़े कि अफगान सरकार को तालिबान को सत्ता में साझीदारी के लिए प्रस्ताव देना पड़ा लेकिन तालिबान ने उसे नकार दिया। अफगानिस्तान में अमेरिका ने धन और हथियार मुहैया कराये पहले सोवियत संघ की फौजों से लड़ने के लिए और बाद में जब उसे लगा कि यह लड़ाई धन और हथियार से नहीं लड़ी जा सकती है तो उसे धर्म की घुड़ी पिलाकर लड़ाया गया जो इस्लाम के नाम पर पूरी दुनिया में अपने लड़ाके भेजने लगे।

जब भारत अपने आजादी का 75वां जश्न मना रहा था तालिबान अपने गानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर रहा था। सबसे हैरानी की बात तो यह रही कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी जिसका दुनिया भर में डंका बजाता है वह भी यह नहीं ताड़ पाई कि तालिबान देश पर कब्जा कर लेगा। अमेरिका के खुफिया एजेंसी ने पांच दिन पूर्व दुनिया को यही बताया था कि यही स्थिति रही तो तालिबान 30 दिन में काबुल पहुंच जायेगा। तीन दिन की कौन कहे तालिबान ने 34 में से 19 प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा करते हुए बहुत ही आसानी से काबुल पर कब्जा जमा लिया। काबुल पर कब्जा जमाते ही देश में जिस प्रकार की अफरातफरी मच गई है कि अफगान नागरिक समझ नहीं पा रहे हैं कि वे क्या करें। जो लोग ग्रामीण इलाकों और तालिबान के कब्जे वाले इलाकों से भागकर काबुल आये थे कि वे यहां सुरक्षित रहेंगे यह देश की राजधानी है जहां कहने को ही सही एक सरकार है उसके मुखिया हैं विभिन्न देशों के दूतावास हैं, सुरक्षित रहेंगे। खुद को बचाने का यह रास्ता भी उनका बन्द हो चुका है। देश के हालातों से बदलाव लोग दूसरे देशों में शरण के लिए परेशान हैं। ऐसी अफरा-तफरी फैली है कि देश के अन्दर कामशियल उडानें पूरी तौर पर बंद कर दी गई हैं और अमेरिका ने अपने छ: हजार सैनिकों की मदद से एअरपोर्ट पर ही कब्जा जमा लिया है जहां से वह अपने नागरिकों, जिन्हें उसने तालिबान के खिलाफ लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया था और कुछ अफगानी नागरिकों जो उनके सम्पर्क में रहे उन्हें ही सुरक्षित देश से बाहर निकालने और दूसरे देशों में पनाह दिलाने के लिए

کشمیر دور ہے، پہلے خود کو بچائے پاک

आदित्य राज कौल

तालिबान के शीर्ष नेताओं मुला बरादर और हक्कानी नेटर्वर्क के सिराजुद्दीन हक्कानी ने कठर एयरफोर्स के विमान से जैसे ही अफगानिस्तान की धरती पर कदम रखा, साफ हो गया कि इस देश में एक नए इस्लामी अमीरात तालिबानी शासन की शुरुआत होने वाली है। काबुल में तालिबान के डिप्टी अनस हक्कानी ने पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और दूसरे नेताओं से मुलाकात की। उन्हें उनकी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त किया। तालिबान के इन कदमों को अपने लिए व्यापक सहमति जुटाने के तौर पर देखा जा रहा है। वह इस बार अपनी एक ऐसी छवि दिखाना चाहता है, जो अधिक मानवीय है।

चरमपंथ बढ़ेगा : काबुल पर कब्जे के बाद से ही तालिबान अपनी एक नरम और उदार छवि पेश करने के लिए बेचैन है। ऐसी छवि, जिसके बारे में उसका दावा है कि यह पहले से बिल्कुल अलग है। तालिबान चाहता है कि लोग उस पुराने चौहरे को भूल जाए, जब सरेआम मौत की सजा दी जाती थी, महिलाओं-लड़कियों के घर से बाहर निकलने पर मनाही थी, बुर्का जैसे शरीर का ही एक अंग बन गया था और लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा तक की इजाजत नहीं थी। हालांकि काबुल के राष्ट्रपति भवन में तालिबान ने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें संकेत दिए गए कि महिलाओं के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सारे अधिकार मिलेंगे उन्हें, लेकिन केवल इस्लामी शरिया कानून के अनुसार। कोई भी शरिया के खिलाफ बोल या लिख नहीं सकेगा। तालिबान की नजरों में यह मुद्दा राष्ट्रीय महत्व का है। इन बयानों से तालिबान की चाल साफ होने लगती है। कुल मामला नई बोतल में पुरानी शराब जैसा है। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा आने वाले वर्त में इस मुल्क को चरमपंथ और आतकवाद का सबसे बड़ा केंद्र बना देगा। तालिबानी शासन के साथ सुन्नी उग्रवाद को मिलेगा एक नया जीवन, जो इस्लामिक राज्य इराक और आईएसआईएस से भी बदतर होगा। तालिबान के पास

खुदरा वितरण

नंतू बनर्जी

देश ने ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में दो

हैं - दीन दयाल उपाध्याय प्राम ज्योति योजना के तहत 100 प्रतिशत गांव विद्युतीकरण और प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण - पूरी तरह से सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के तहत। हालांकि, इन गरीब समर्थक योजनाओं ने शायद ही बिजली की मांग को बढ़ाया। हालांकि भारत चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक देश है, लेकिन प्रति व्यक्ति खपत के मामले में यह बहुत नीचे है। बिजली (संशोधन) विधेयक, 2021 की तैयारी के पीछे जो भी हो, पहल करने वालों ने एक साधारण तर्क को नजरअंदाज कर दिया है कि भारत को अपनी वितरण नीति को फिर से तैयार करने से पहले अपने लोगों के लिए पर्याप्त बिजली पैदा करने का प्रयास करना चाहिए। उपभोक्ताओं को बिजली की लागत का पहलू भी किसी भी नई बिजली नीति को तैयार करने में सासदों का मार्गदर्शन करना चाहिए। जबकि बिल पहली बात को पहचानने में विफल है। उत्पादन क्षमता में तेजी से वृद्धि की आवश्यकता है, जबकि यह निजी भागीदारी के माध्यम से चयनात्मक वितरण से अधिक संबंधित है। ऐसा लगता है कि दस्तावेज़ को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जो

तालिबानों की गिरफ्त में अफगानिस्तान, बना बुजकशी का मैदान

डॉ सुमन गुप्ता

आमजन को वहां से दूर रखा है। एउपोर्ट पर बढ़ती भीड़ को हटाने के लिए अमेरिकी सैनिकों की गोलियां से पांच लोगों के मरने और कई के हताहत होने के खबर हैं। वहाँ हवाई जहाज पकड़ने के लिए सीधियों के रास्ते पर लोग इस कदर लद्द-फदर दिखाई दे रहे हैं कि उनकी बदहवासी, बैचेनी, देश को छोड़ने की बेताबी साक नजर आ रही है। कुछ लोग जो छिपकर हवाई जहाज के कुछ हिस्से में बैठ गए थे वे उसके उड़ते ही जमीन पर गिरते नजर आये। तालिबानी प्रवक्ता अब्दुल बरादर का कहना है कि हम तो जितना कठिन समझते थे काबुल तक पहुंचना वह तो बहुत आसान साबित हुआ, ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते थे। इसका सीधा अर्थ यही है कि सेना और पुलिस के लोग भी उनके सामने लड़ने के बजाय सरेंडर करते जा रहे थे। जब देश का राष्ट्रपति ही देश छोड़कर भाग जाए तो वे कर भी क्या सकते थे। यहीं हालात दूसरे देशों के सामने भी पैदा हो गये कि वे अफगानिस्तान को वहां के नागरिकों के भरोसे छोड़ दें वहाँ जो कुछ हो रहा है होने दें या फिर हस्तक्षेप करें तो किसके लिए क्योंकि पूरे देश पर तालिबान का कब्जा हो गया है। मार-काट मचाते हुए उन्होंने एक-एक करके सभी प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा करके देश की राजधानी काबुल पर भी कब्जा करके यह दिखा दिया है कि अब इस देश में हमारा राज है हमारा ही कानून चलेगा। तालिबान का कूर बर्बर घेहरा दृष्टिया ने देखा है। इस्लाम और जेहाद के नाम पर वह कुछ भी करके सही साबित करने की कोशिश करते आये हैं वह चाहे महिलाओं का जीवन हो, पत्रकार उनके विरोधी या हजारा, उज्जेक आदि जिन्हें वे अफगानी मानने से ही मना करते आये हैं और उन्हें देश छोड़कर जाने के लिए चेतावनी देते आये हैं। अमेरिका ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वह अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुला लेगा। इसके पहले वह अफगानी सैनिकों को तालिबानों से लड़ने के लिए ट्रेनिंग देकर इस स्तर का बना देगा कि वे स्वयं उनसे मुकाबला कर सकें। विश्व के सर्वशक्तिशाली देश अमेरिका की सैन्य ट्रेनिंग धरी की धरी रह गई। कहीं, यह किसी गुप्त नीति और समझौते का हिस्सा तो नहीं है जो दुनिया के सामने नहीं आ पाया है? 9/11 के वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हुए हमले के बाद ओसामा बिन लादेन और उसके संगठन को जिम्मेदार बताते हुए पाकिस्तान में छिपे ओसामा बिन लादेन को पकड़कर मारकर उसकी लाश को समुद्र में डुबोकर क्या अमेरिका ने मान लिया कि अब सब कुछ ठीक हो गया। जिस जिज्ञ को उसने पैदा किया था क्या वह बोतल में बंद रहकर खत्म हो गया या बोतल से बाहर आकर नाच रहा है। सोवियत फौजों के अफगानिस्तान में आने के साथ ही उन्हें देश से बाहर करने के लिए मुजाहिदीनों ने छापामार शैली में युद्ध छेड़ दिया था जिन्हें ट्रेनिंग पाकिस्तान एवं शरणार्थी शिविरों में दी गई। विभिन्न रिपोर्टों को देखा जाए तो मुजाहिदीनों को अमेरिका, अमेरिकी खुफिया एजेंसी के साथ ही अरब देशों, ब्रिटेन ने भी आर्थिक सहायता और हथियार, साजो सामान उपलब्ध कराये। सोवियत संघ के स्वयं धराशायी होने के प्रक्रिया के दौरान ही रूसी राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव जो ग्लासनोस्त पेरोइस्त्रका को अपनाने के साथ ही अपने ही देश के टुकड़े-टुकड़े कर भैं। अफगानिस्तान से सोवियत सेनाओं की वापसी की प्रक्रिया 15 मई 1988 से शुरू हुई जो 1989 तक चलती रही। सोवियत फौजों के जाने के साथ ही अफगानी सरकार मुजाहिदीनों से लड़ने में अकेले पड़ गई। अफगानिस्तान की खनिज सम्पदा को लेकर अमेरिका की रुचि बनी रही। अफीम और हथियार दोनों ने मुजाहिदीनों और तालिबानों को इतनी ताकत दुनिया के कुछ खास देशों ने दी जिसका भुक्तभोगी अमेरिका भी हो गया। 2001 में जब उसके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर चार विमानों के हाईजैक के साथ एक साथ पैंटागन और सेंटर पर हमला हुआ तो वह चैतन्य हुआ और अफगानिस्तान में आतंकवाद मिटाने के नाम पर पहुंच गया और पाकिस्तान को आर्थिक और युद्ध के साजो सामान की सहायता देता रहा। अफगानिस्तान के आतंकीयों से निपटने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को एक महत्वपूर्ण केन्द्र बनाया इसके लिए पाकिस्तान की सम्भूता से खिलाड़ी करके उसके यहां रह रहे ओसामा बिन लादेन को बिना पाकिस्तान की अनुमति के खींच कर मार दिया और समुद्र में डाल दिया। यहीं नहीं, आतंकवाद के खात्मे के नाम पर उसने पाकिस्तान में अपने ड्रोन से हमले किए। पाकिस्तान आतंकवाद के नाम पर अमेरिका से मोटी रकम और साजो सामान भी वसूलता रहा और तालिबानों को सहायता भी देता रहा। काबुल पर तालिबानों के कब्जे के बाद पाकिस्तान, चीन और ईरान ने तालिबानों को समर्थन दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि अफगानिस्तान में इन दिनों जो कुछ हो रहा है वह गुलामी की जंजीरों को तोड़ने जैसा है। भारत के सामने यह संकट है कि अफगानिस्तान के साथ कैसा सम्बन्ध रखें। वहीं, पाकिस्तान और चीन तालिबान का साथ देकर भारत को अलग-थलग करना चाहेंगे। तालिबान का अफगानिस्तान में सत्ता में आना इस क्षेत्र के लिए खतरे की घटी है। तालिबान, पाकिस्तान और चीन का गठजोड़ हो सकता है वहीं, मुस्लिम देशों का भी उसे समर्थन प्राप्त हो सकता है। अभी तक उसका अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना सम्बन्ध रहा, तालिबानों की सरकार बनने के बाद उसे विभिन्न देशों द्वारा मान्यता देने का प्रश्न भी आयेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने भी यह प्रश्न विचारणीय होगा। एक देश को बर्बाद करने में जिस प्रकार सोवियत संघ और अमेरिका का योगदान रहा उससे यह देश तहस-नहस हो चुका है। बमबारी, हमलों से क्षति-विक्षत वहां के लोग कोई रास्ता स्वयं निकाल सकेंगे, यही आखिरी उम्मीद की जा सकती है।

भोजपुर के पहिलका बागी महाराजा फतेह साही

मुन्ना क. पाण्डय

'अइसन वार न सुनलो कान / जान म ना कहा जनाइला।'- सन 1765 ई. में जब शाह आलम बिहार, बंगाल आ उड़ीसा के दीवानी अंग्रेजन के साँप दिल्लन तब सारन के कलेक्टर हस्सेपुर (बिहार के गोपालगंज जिला) के महाराज फतेह बहादुर साही से राजस्व के मांग किल्स आ उनकरा से कंपनी के अधीनता स्वीकार करे के बात भी कहलस। फतेह बहादुर साही इ दुनु बात माने से इंकार कर दिल्ले। सारण प्रान्त के एह इलाका में लगभग तेर्झस बरस तक फतेहबहादुर साही अंग्रेजन से युद्ध करत रहले, कबो सीधे सामने

गो बचाए पाक

ने कई समझौते तो दिए। उसके लड़ाके एक के बाद एक राज्यों पर जबरन कब्जा करते हुए राजधानी तक पहुंच गए। काबुल में आत्मघाती हमले जारी रहे। मासूमों को निशाना बनाया जाता रहा। अगर तालिबान ने दोहा वार्ता की शर्तों के मुताबिक कदम बढ़ाए होते तो पाकिस्तान परिस्थिति का फायदा उठाने की ज़्यादा अच्छी स्थिति में होता। अब अमेरिका भी पहले की तरह उस पर अधिक निर्भर नहीं रहेगा। वैसे पाकिस्तान पर्दे के पीछे से इस तालिबानी शासन में अपना उचित हिस्सा चाहता है।

तालिबान से बातचीत : अगर भारत की बात करें तो वह इस क्षेत्र की हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकता। अगर तालिबान के साथ बैकचैनल से बातचीत नहीं चल रही है, तो शुरू करनी होगी। भारत की एक बड़ी आबादी मुस्लिम है और तालिबान इसे नजरअंदाज नहीं करेगा। वह जम्मू-कश्मीर और भारत के दूसरे आंतरिक मामलों में टांग अड़ाने के बजाय भारत से सीधी बातचीत चाहेगा। तालिबान की आधिकारिक नीति है कि जम्मू-कश्मीर एक द्विपक्षीय मसला है। इसी से कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मामले में उसके दृष्टिकोण का पता चल जाता है। यह दृष्टिकोण अब तक भारत के अनुकूल रहा है और लगता नहीं कि अफगानिस्तान में अपने शासन को मजबूत किए बिना तालिबान संघर्ष का कोई नया मोर्चा खोलेगा। हालांकि इन सबके बावजूद भारत को जम्मू-कश्मीर को लेकर सतर्क रहना होगा। हाल-फिलहाल भल नहीं, लेकिन आने वाले समय में आतंकवाद में वृद्धि देखी जा सकती है। तालिबान के उदय ने जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों में नई ऊर्जा भर दी है। इन संगठनों के अफगानिस्तान में आतंकी शिविर हुआ करते थे। 1990 के दशक में कश्मीर में घुसपैठ करने वाले आतंकियों का मुल्ला उमर के कैंप में ट्रेनिंग मिली होती थी। अफगान और अमेरिकी सेना के खिलाफ पाकिस्तानी आतंकियों के लड़ने के जज्बे को भी तालिबान नहीं भूला होगा। तो कुल मिलाकर जब तक भारत इस नई स्थिति का विश्लेषण करता है, तब तक तालिबान के सामने भी कई चुनौतियां हैं। उसे समझना होगा कि शासन कैसे करना है और जातीय रूप से बंटे देश को किस तरह एक करके रखा जाए।

खुदरा वितरण से पहले निजी

सामान्य रूप से बिजली जनरेटर से अधिक निजी वितरकों (डिस्कॉम) के एक चुनिंदा समूह को लाभान्वित करता है। आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार की खुद की स्वीकृति में, बिजली क्षमता वृद्धि में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी घट रही है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि 2019-20 में बिजली क्षेत्र में स्थापित उत्पादन क्षमता पूरी तरह से सरकार द्वारा संचालित थी, जबकि निजी क्षेत्र एक भी इकाई जोड़ने में विफल रहा।

तकनीकी रूप से, केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और वितरण के संबंध में कोई भी कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है क्योंकि यह क्षेत्र संविधान की समर्वता सूची के अंतर्गत आता है। हालांकि, गैर-भाजपा शासित राज्यों की एक अच्छी संख्या परेशान है। संविधान के तहत, किसी भी राज्य की विधायिका को समर्वता सूची के तहत किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति भी है। कुछ राज्यों ने मांग की है कि विधेयक को संसद की प्रवर समिति के पास भेजा जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि विधेयक को गलत तरीके से तैयार किया गया है क्योंकि विपक्षी राज्यों को बिजली उत्पादन और वितरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर

विषयों पर राजनीति का विवाद आरपाद्यन तथा भवत्पूर्व उद्धरण से बाहर रखा गया है। भारत की प्रति व्यक्ति बिजली की खपत के अनुसार, किलोवाट घंटे के मामले में, देश राष्ट्रों के समदाय में 13वें स्थान पर है। आज, भारत की जनसंख्या लगभग उतनी ही है जितनी कि चीन की। चीन में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत लगभग 5,000 यूनिट है जबकि भारत में 1,000

यूनिट से कम है। चीन अब तक दुनिया का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक देश है, जो 2019 में कोयले और पनबिजली के माध्यम से अपनी बिजली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पैदा कर रहा है, जबकि भारत में यह केवल 1,559 है। बिजली की खपत में भी चीन दुनिया में सबसे ऊपर है, जो सालाना 6.3 ट्रिलियन किलोवाट ऊर्जा प्रति घंटे से अधिक का उपयोग करता है। देश दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक और उपभोक्ता है। देर से ही सही, चीन ने आंशिक रूप से अपना ध्यान प्राकृतिक गैस और नवीकरणीय स्रोतों पर स्थानांतरित कर दिया है। इस संदर्भ में, भारत में एक नए बिजली बिल का अत्यधिक स्वागत किया जाता अगर यह बिजली उत्पादन को एक बिंग पूश देने की मांग करता और देश के सार्वजनिक क्षेत्र, राज्य क्षेत्र और निजी क्षेत्र के लिए उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करता। बिजली की मांग बढ़ाने के लिए, बिल ग्रामीण, कृषि, घरेलू, निर्यात और सामान्य औद्योगिक उपयोगकर्ताओं सहित विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम खुदरा वितरण दरों के लिए लक्ष्य तय करके बिजली मूल्य निर्धारण पहलू से भी निपट सकता था। बिजली बिल उच्च खुदरा बिजली दरों को रोकने के लिए बहुत कम प्रदान करता है, विशेष रूप से निजी क्षेत्र की डिस्कॉम द्वारा, अडानी, रिलायंस इंफ्रा, सीईएससी और टाटा के नेतृत्व में। भारत में उच्च खुदरा बिजली दरों का देश की कम उत्पादन लागत के साथ बहुत कम संबंध है। वास्तव में, भारत पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में कोयले, सौर और पवन स्रोतों से

बिजली का सबसे सस्ता उत्पादक है। यह इस क्षेत्र का एकमात्र देश है जहां सौर ऊर्जा की लागत ताप विद्युत की तुलना में लगभग 14 प्रतिशत कम है। फिर भी, भारतीय उपभोक्ताओं को मलेशिया, वियतनाम और चीन जैसे देशों सहित इस क्षेत्र में सबसे अधिक बिजली दरों का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है। वैश्विक सलाहकार वुड मैकेज़ी के अनुसार, भारत में जीवाश्म ईंधन से लगभग 44.5 डॉलर प्रति मेगावाट (3.05 रुपये प्रति यूनिट) की बिजली उत्पादन की लागत इस क्षेत्र में सबसे सस्ती है। चीन में, यह क्षेत्र के अन्य 12 देशों में 48.5 डॉलर प्रति मेगावाट (3.33 रुपये प्रति यूनिट) और ऑस्ट्रेलिया 50.9 डॉलर प्रति मेगावाट (3.49 रुपये प्रति यूनिट) है। सौर ऊर्जा के लिए भी यही है। भारत में, लागत लगभग 38.2 मेगावाट (2.62 रुपये प्रति यूनिट) होने का अनुमान है, जो सबसे कम है। ऑस्ट्रेलिया में यह 52.7 डॉलर प्रति मेगावाट (3.62 रुपये प्रति यूनिट) और चीन में 61.2 डॉलर प्रति मेगावाट (4.2 रुपये प्रति यूनिट) है। भारत की तटवर्ती पवन ऊर्जा उत्पादन की अनुमानित लागत 48.9 डॉलर प्रति मेगावाट (3.36 रुपये प्रति यूनिट) है, जो इस क्षेत्र में सबसे सस्ती है। अधिकांश श्रेय एनटीपीसी लिमिटेड के नेतृत्व में भारत की सरकार द्वारा नियंत्रित बिजली उत्पादन फर्मों को जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल, केरल और दिल्ली सहित अधिकांश विपक्षी राज्यों का मानना है कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र की डिस्कॉम को लाभ पहुंचाना है।

